International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 01, January - March, 2021, pp.340-348

शासकीय योजनाओं का जनजातियों के शैक्षणिक विकास पर प्रभावः राजस्थान की सहरिया जनजाति के संदर्भ में

किशना राम चौधरी*
अरुणा कौशिक**
सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ***

lkj

सहरिया जनजाति राजस्थान की सबसे अधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक है, यह राज्य में केवल बाराँ जिले के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में ही मुख्य रूप से निवास करती है। इनके निवास स्थान सुदूर वन–क्षेत्रों, बंजर तथा पथरीली भूमि में स्थित है। भारत की स्वतंत्रता के 74 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी यह जनजाति वर्तमान में एक आदिम समाज की भाँति जीवन यापन कर रही है। इस शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य जनजातियों के शैक्षणिक विकास से संबंधित संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभावों की जाँच सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के संदर्भ में करना है। यह अध्ययन प्राथमिक तथा द्वितीयक समंकों पर आधारित है। जिसमें प्रतिदर्श का आकार 200 सहरिया परिवारों का है इन सहरिया परिवारों का यादृछिक प्रतिचयन की रीति से चयन करके गूगल फॉर्म के जरिये प्रश्नावली तथा प्रत्यक्ष क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक समंकों का संकलन किया गया है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं का प्रदर्शन कैसा रहा है? साथ ही में यह शोध–पत्र इस बात की भी जाँच करता है कि राजस्थान के सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में से कौन–सी योजनाएँ बेहतर प्रदर्शन कर रही है और कौन–सी योजनाएँ किन कारणों से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। इन कारणों की खोज करके उनके उचित समाधान हेतु सुझाव दिए गए है। जिससे कि सहरियों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि लाई जा सकें।

'kCnkoyh% *सहरिया, जनजातीय समूह, शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक योजनाएँ, शैक्षणिक उत्प्रेरक*

———————————————————

प्रस्तावना

'जनजाति' शब्द का अर्थ ऐसे समाज या समाज के उस हिस्से से है जिसके सदस्य सामान्य तौर पर रीति–रिवाज, विश्वास और नेतृत्व आदि के संदर्भ में एक ही वंश से सम्बन्धित होते है। अन्य शब्दों में, जनजाति को ऐसे लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि एक समान व्यवसाय, सामाजिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक दृष्टिकोण से सम्बन्ध रखते है। संसार की अधिकांश जनजातियाँ वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, ये वन क्षेत्रों में निवास करती है और उनकी आजीविका वन–उत्पादों तथा पशुपालन पर निर्भर करती है। अपनी घुमन्तु प्रवृत्ति के चलते इनमें से अधिकांश जनजातियाँ एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमती रहती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रूप में किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद – 342 के अनुसार अनुसूचित है। इस अनुच्छेद के अनुसार वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए

G सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान।
** प्राचार्य, राजकीय कन्या, महाविद्यालय बाँरा, राजस्थान।
*** सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान।

अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे आदिवासी समुदायों के लिए 'अनुसूचित जनजाति' शब्द का प्रयोग संवैधानिक रूप से किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत भारत में सात सौ से अधिक आदिवासी समुदायों को 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में अधिसूचित किया गया है।

इनमें से कुछ समुदाय आदिम ढंग की विशेषताओं वाले हैं। इन आदिम समूहों में घटती हुई या स्थिर जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, कृषि–पूर्व स्तर की प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक पिछड़ेपन की विशेषताएँ विद्यमान हैं ये सभी समूह आर्थिक रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्ग है। स्वतंत्रता के 74 वर्षों के उपरांत भी ऐसे आदिम समुदायों के अधिकांश लोग शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति के पर्याप्त स्तर को हासिल नहीं कर पाए है और उनका स्वास्थ्य सूचकांक अत्यंत न्यून स्तर का बना हुआ है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने राजस्थान सहित 18 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में बसे हुए ऐसे 75 आदिम समुदायों की पहचान कर उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की श्रेणी में रखा है। सहरिया आदिम समुदाय एक ऐसा ही विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) है जो मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में बसा हुआ है।

Hkkjr esa tutkfr;ksa dh 'kS{kf.kd dh fLFkfr

भारत के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक विकास काफी असमान है। जनजातीय साक्षरता दर सघन जनजातीय आबादी के सकेन्द्रण वाले राज्यों में अपेक्षाकृत बहुत ऊँची है जैसे कि– मिजोरम (91.5%), नागालैंड (80.0%), मेघालय (74.5%) तथा मणिपुर (72.6%)। जबकि देश की अधिकांश जनजातीय आबादी वाले राज्यों का प्रदर्शन जनजातीय साक्षरता दर की दृष्टि से अपेक्षाकृत अत्यंत चिंताजनक है जैसे कि– आंध्रप्रदेश (49.2%), मध्यप्रदेश (50.6%), ओड़िसा (52.2%), राजस्थान (52.8%) तथा झारखण्ड (57.1%)। सारणी–1.1 तथा रेखाचित्र–1.1 को देखने से यह स्पष्ट होता है कि पिछले छः दशकों के दौरान समग्र भारत तथा जनजातीय साक्षरता दर की तुलना की जाये तो दोनों के मध्य पाया जाने वाला अन्तराल काफी अधिक है, परन्तु पिछली तीन जनगणनाओं के दौरान इस अन्तराल में आई गिरावट ने सरकारी प्रयासों की सफलता को सार्थक सिद्ध किया है।

lkj.kh 1% lexz Hkkjr rFkk vuqlwfpr tutkfr dh rqyukRed lk{kjrk nj ¼çfr'kr esa½

J`.kh@tux.kuk o"kZ	1961	1971	1981	1991	2001	2011
lexz tula[;k	28.3	34.45	43.57	52.21	64.84	72.99
vuqlwfpr tutkfr	8.53	11.30	16.35	29.60	47.10	58.96
vUrjky	19.77	18.15	19.88	22.61	18.28	14.03

Source: Statistical profile of Scheduled tribes in India 2013, Section -02, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, P. No. 13, (www.tribal.nic.in)

js[kkfp= 1% lexz Hkkjr rFkk vuqlwfpr tutkfr dh rqyukRed lk{kjrk nj ¼çfr'kr esa½

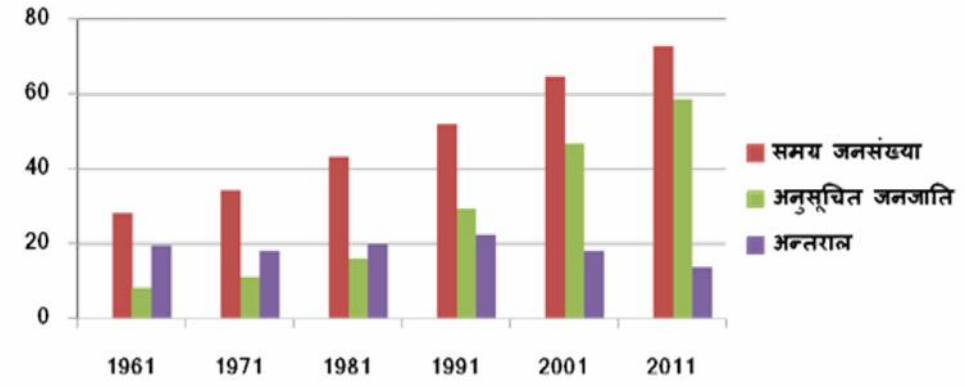

lgfj;k tutkfr dh 'kS{kf.kd fLFkfr

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सभी अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए जो प्रयास किये गये उनमें सहरिया जनजाति भी अछूती नहीं है परन्तु यह आदिम जनजाति देश के विशेष रूप से कमजोर समूहों में से एक है जो इन सरकारी प्रयासों से अपनी अज्ञानता, निर्धनता, भोलेपन तथा शर्मीलेपन के चलते उतना लाभ अर्जित नहीं कर पाई जितना कि अन्य दूसरी जनजातियों ने प्राप्त किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर समग्र जनजातियों के लिए साक्षरता की दर 58.96% है जबकि समग्र जनजातियों के लिए पुरुष तथा महिला साक्षरता की दर क्रमशः 68.53% तथा 49.35% है। सहरिया जनजाति की बसावट वाले राज्यों की राज्य स्तर पर समग्र जनजातियों तथा सहरिया साक्षरता दरों का तुलनात्मक विवरण सारणी 1.2 में दिया गया है–

lkj.kh 2% jkT;okj lk{kjrk nj ¼çfr'kr e½						
jkT;@lk{kjrk	lexz vuqlfpr tutkfr;k¡			lgfj;k tutkfr		
	iq#"k	efgyk	dqy	iq#"k	efgyk	dqy
छत्तीसगढ़	69.7	48.8	59.1	90.8	68.3	80.9
राजस्थान	67.6	37.3	52.8	61.9	33.7	48.0
मध्यप्रदेश	59.6	41.5	50.6	51.7	32.0	42.1
Source: Statistical profile of Scheduled tribes in India 2013, Ministry of Tribal Affairs, Government of India, (www.tribal.nic.in)						

उपर्युक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि अपवाद स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को छोड़कर राजस्थान तथा मध्यप्रदेश राज्यों में सहरिया आदिम जनजाति शैक्षणिक विकास दृष्टि से अन्य जनजातियों की अपेक्षा अधिक पिछड़ी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में सहरिया जनजाति की बहुत कम आबादी बसी हुई है। जबकि इनकी 95% से अधिक आबादी राजस्थान तथा मध्यप्रदेश राज्यों में ही निवास करती है। राजस्थान में यह जनजाति केवल राज्य के दक्षिणी–पूर्वी भाग में स्थित बाँरा जिले की किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में बसी हुई है। यह राज्य की एकमात्र विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) की श्रेणी वाली जनजाति है, जो समग्र विकास की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़ी हुई जनजाति मानी जाती है। इनके शैक्षणिक उत्थान के लिए राजस्थान में अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है।

mís';

प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान की सहरिया जनजाति पर आधारित है जो इस जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की भूमिका का किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में तुलनात्मक अध्ययन करता है। अतः प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य दोनों तहसीलों के संदर्भ में सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की निम्न जाँच करना है–

- शैक्षणिक विकास की योजनाओं के सम्बन्ध में सहरिया जनजाति के लोगों की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले सहरिया परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- इन योजनाओं से सहरिया जनजाति के लोगों के शिक्षा के स्तर, उनके अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना।

lkfgR; flgkoykdu

भारत में पिछड़े वर्गों– विशेषकर आदिवासी समुदायों के समुचित उत्थान के लिए अनेक प्रोजेक्ट तथा कार्यक्रम अपनाये गए। भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा समय–समय पर इन परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रभावों का विश्लेषण तथा आनुभविक अध्ययन आयोजित किया गया।

of t;fu; l tXlk ¼2015½ के अनुसार औपनिवेशिक काल में आदिवासी समूहों के लिए केवल सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करने के अलावा उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किये गये। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने औपनिवेशिक काल की नीति में थोड़ा–सा संशोधन करके जारी इसे रखा और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य प्रायोजित शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी सेवाओं में 7.5 प्रतिशत सीटें इनके लिए आरक्षित कर दी। इन प्रावधानों ने जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं का एक बड़ा पूल खोल तो दिया, परन्तु इनकी शैक्षिक अयोग्यता तथा आवश्यक न्यूनतम कौशल की कमी ने उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित रखा और अधिकतर मामलों में इनके लिए आरक्षित सीटें सदैव ही रिक्त रही है। v#.k dekj ?kks"k ¼2007½ ने अपने शोध पत्र में पश्चिम बंगाल की 'लोढ़ा' तथा झारखंड की 'हो' एवं 'महाली' जनजातियों में निम्न साक्षरता के कारणों की विस्तृत चर्चा करते हुए, यह बताने का प्रयास किया कि इन आदिवासी समुदायों में नामांकन अनुपात के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत उच्च लैंगिक विषमता व्याप्त है। ';key dekj njhik ¼2017½ ने भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आदिवासी समुदायों की शैक्षणिक उन्नति के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों तथा उनके परिणामस्वरूप इन समुदायों में उत्पन्न शैक्षणिक माहौल का द्वितीयक समंकों के आधार पर विश्लेषण किया है। भारत के सभी समुदायों तथा आदिवासी समुदायों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट किया कि आज भी अनुसूची जनजातियों की शैक्षिक स्थिति में वृद्धि तथा साक्षरता दर अपेक्षाकृत अत्यंत निम्न स्तर की है। uhjk xkÜke ¼2013½ ने भारत में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं तथा कार्यकमों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा पर विचार प्रकट करते हुए इस बात पर बल दिया कि शिक्षा आदिवासी समुदायों का न केवल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, बल्कि यह उनके समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करता है। हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन का मूल कारण निरक्षरता ही है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से उनके शैक्षणिक मानकों में सुधार करने के लिए प्रयासरत् है। परन्तु जनजातियों की निम्न साक्षरता को बार–बार नये कार्यक्रमों तथा योजनाओं को लागू करके हल नहीं किया जा सकता है।

'kks/k&çfof/k

प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान की सहरिया जनजाति पर आधारित है जिसमें सहरिया जनजाति के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान लिए संचालित बारह अलग–अलग तरह की शैक्षणिक योजनाओं का किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। राजस्थान की सहरिया बाहुल्य तहसीलों – किशनगंज तथा शाहाबाद में से प्रत्येक तहसील से पाँच–पाँच गाँवों का चयन स्तरित प्रतिचयन की रीति के माध्यम से कर, प्रत्येक चयनित ग्राम में से 20–20 परिवारों अर्थात् प्रत्येक तहसील से 100 परिवारों तथा कुल 200 परिवारों का यादृच्छिक रीति से चयन किया गया है। इस प्रकार 200 परिवारों का प्रतिदर्श लेकर गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रश्नावली तथा इनके क्षेत्रों में जाकर साक्षात्कार अनुसूची के जरिए प्राथमिक समंकों का संकलन किया गया है। प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार अनुसूची में प्रश्नों का निर्माण मापक्रम (Scale), संज्ञात्मक (Nominal) तथा क्रमवाचक (Ordinal) पैमाने के आधार पर किया गया है। एकत्रित समंकों की कमियों, अशुद्धियों तथा अनियमितताओं को यथोचित मात्रा में ठीक करते हुए उन्हें समानता तथा सजातीयता के आधार पर विभिन्न वर्गों तथा समूहों में वर्गीकृत करते हुए क्रॉस सारणीयन तथा रेखाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। समंकों के विश्लेषण के लिए S.P.S.S. सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिशत विधि का उपयोग किया है।

fo'ys"k.k

राजस्थान में सहरिया आदिम समुदाय के बालक– बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं को मौटे रूप में तीन श्रेणियों– शैक्षणिक विकास से सम्बन्धित योजनाओं, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरक से सम्बन्धित योजनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन

सभी योजनाओं का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान सरकार के निर्देशन में सहरिया परियोजना अधिकारी, शाहाबाद की देखरेख में किया जा रहा है। लक्षित उत्तरदाताओं से इन सभी योजनाओं की जानकारी तथा लाभ के बारे में प्रश्न पूछने पर निम्न परिणाम प्राप्त हुए है–

lkj.kh 3½ lgfj;k tutkfr d 'k{kf.kd fodkl l lEcfU/kr ;ktukvk dh fLFkfr								
;ktuk,¡	fd'kuxat ¼100½				'kkgkckn ¼100½			
	tkudkjh		ykHkkfUor		tkudkjh		ykHkkfUor	
	gk¡	ugha	gk¡	ugha	gk¡	ugha	gk¡	ugha
'k{kf.kd fodkl l lEcfU/kr ;ktuk,¡								
माँ–बाड़ी केंद्र	94	06	90	10	97	03	93	07
आश्रम छात्रावास	72	28	41	59	90	10	43	57
आवासीय विद्यालय	69	31	31	69	53	47	33	67
एकलव्य मॉडल स्कूल	46	54	06	94	75	25	08	92
çkFkfed Lrj d fo|kfFkZ;k dk 'k{kf.kd mRçjd l lEcfU/kr ;ktuk,¡ ¼d{kk& I l V½								
मुफ्त स्टेशनरी वितरण	93	07	91	09	94	06	93	07
मुफ्त पोशाक वितरण	93	07	91	09	94	06	93	07
ek/;fed Lrj d fo|kfFkZ;k dk 'k{kf.kd mRçjd l lEcfU/kr ;ktuk,¡ ¼d{kk& VI l XII½								
मुफ्त स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फीस वितरण	74	26	71	29	84	16	71	29
सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता	31	69	25	75	58	42	32	68
सहरिया छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण	18	82	10	92	47	53	19	81
सहरिया छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण	18	82	06	94	36	64	01	99
प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति	72	28	67	33	82	18	68	32
उपस्थिति प्रोत्साहन	73	27	67	33	83	17	69	31

;ktukvk d ckj e tkudkjh

सारणी 3 से स्पष्ट होता है कि राजस्थान के सहरिया क्षेत्रों में शैक्षणिक विकास से सम्बन्धित संचालित कुल चार योजनाओं में से पहली तीन – माँ बाड़ी केंद्र, आश्रम छात्रावास तथा आवासीय विद्यालय अत्याधिक चर्चित योजनाएँ है। इन तीनों योजनाओं के संचालन की जानकारी दोनों तहसीलों– किशनगंज तथा शाहाबाद की 50% से अधिक आबादी को है जबकि एकलव्य मॉडल स्कूल के संचालन की जानकारी किशनगंज (46%) की अपेक्षा शाहाबाद (75%) के सहरिया लोगों को अधिक है, इसका मुख्य कारण यह मॉडल स्कूल शाहाबाद में संचालित है। इन चारों योजनाओं में से दोनों तहसीलों में सबसे अधिक तथा सबसे कम चर्चित योजनाएँ क्रमशः माँ–बाड़ी केंद्र तथा एकलव्य मॉडल स्कूल है। जबकि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरक से सम्बन्धित दोनों योजनाएँ– मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा– I से V) तथा मुफ्त पोशाक वितरण (कक्षा– I से V) दोनों ही तहसीलों में उत्कृष्ट स्तर पर प्रचलित है इन योजनाओं के संचालन की जानकारी दोनों ही तहसीलों की 90% से अधिक आबादी को है। जहाँ एक ओर माध्यमिक स्तर (कक्षा– VI से XII) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरक से सम्बन्धित तीन योजनाओं – मुफ्त स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फीस वितरण, प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति तथा उपस्थिति प्रोत्साहन के बारे में किशनगंज तथा शाहाबाद के क्रमशः 70% तथा 80% से अधिक सहरिया जनजाति के लोग जानकारी रखते है। वहीं दूसरी ओर इस श्रेणी के अंतर्गत विशेषरूप से सहरिया जनजाति की छात्राओं के लिये संचालित तीन योजनाओं–सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता राशि, निःशुल्क साइकिल (कक्षा– IX से XII), तथा स्कूटी के वितरण की जानकारी के सम्बन्ध में दोनों तहसीलों की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है

j[kkfp= 2% fd'kuxat esa 'kS{kf.kd fodkl ls lEcfU/kr ;kstukvksa dh tkudkjh

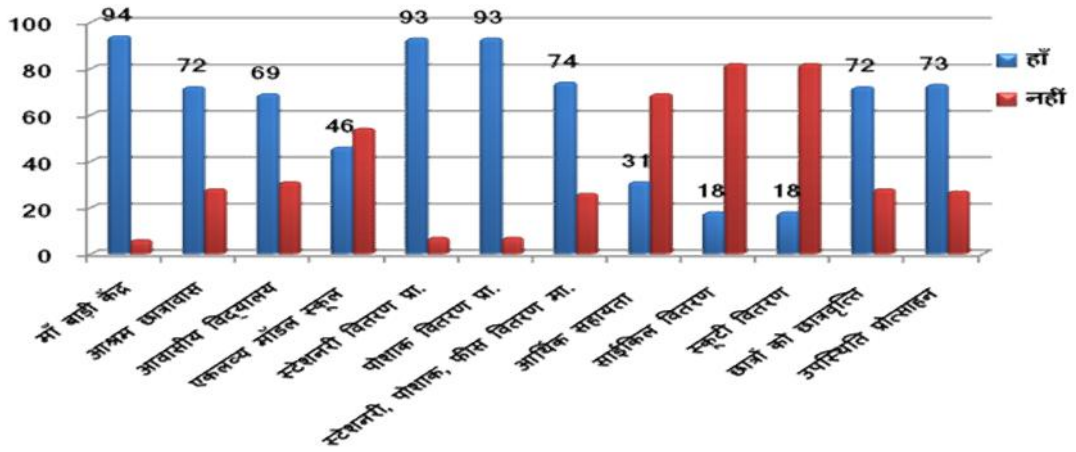

क्योंकि इन तीनों योजनाओं के बारे में किशनगंज तहसील के क्रमशः 31%, 18% तथा 18% और शाहाबाद तहसील के क्रमशः 58%, 47% तथा 36% सहरिया लोग इन योजनाओं के संदर्भ में जागरुक है। इस प्रकार रेखाचित्र 2 तथा रेखाचित्र 3 का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर (कक्षा– IX से XII) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरक से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं की जानकारी रखने के सम्बन्ध में शाहाबाद की स्थिति किशनगंज की अपेक्षा कहीं अधिक बेहतर है।

j[kkfp= 3% 'kkgkckn esa 'kS{kf.kd fodkl ls lEcfU/kr ;kstukvksa dh tkudkjh

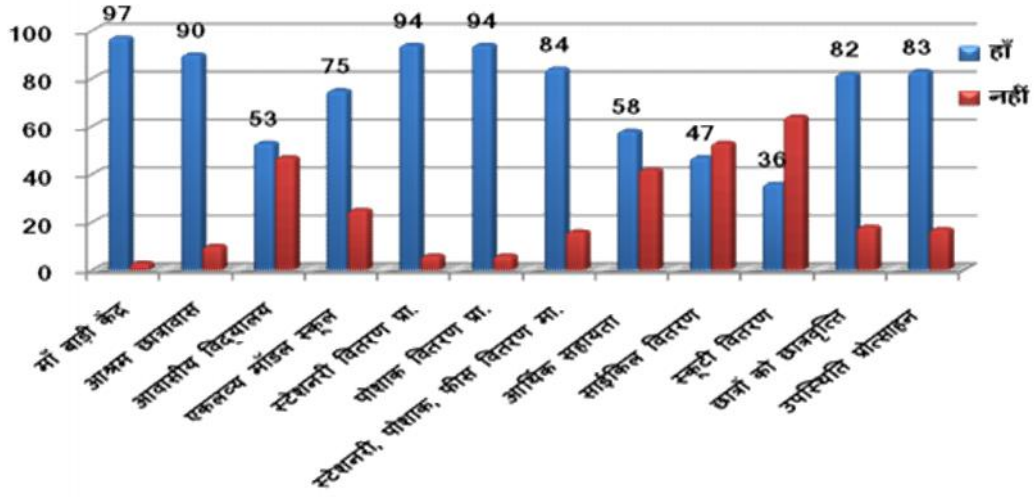

;kstukvksa ls ykHkkfUor

योजनावार लाभार्थियों की संख्या की दृष्टि से दोनों तहसीलों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि शैक्षणिक विकास की उपर्युक्त योजनाओं का प्रदर्शन दोनों तहसीलों में अलग–अलग रहा है और इनसे लाभ अर्जित करने वाले लाभार्थियों की संख्या में भी पर्याप्त विषमताएँ विद्यमान है। रेखाचित्र 4 तथा रेखाचित्र 5 को देखने पर स्पष्ट होता है कि दोनों तहसीलों में माँ–बाड़ी केंद्रों के संचालन, मुफ्त स्टेशनरी तथा पोशाक वितरण (कक्षा– I से V तक) की योजनाओं से

j[kkfp= 4% fd'kuxat e 'k{kf.kd fodkl ls lEcfU/kr ;kstukvksa ls ykHkkfUor

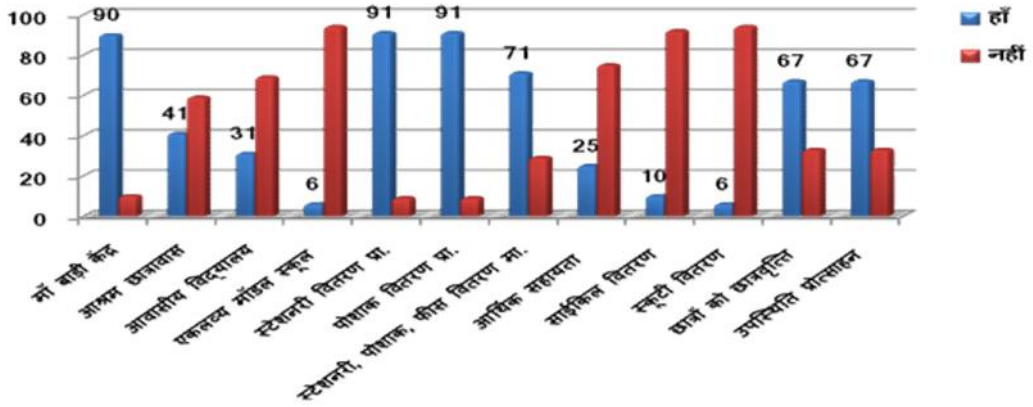

90% से अधिक सहरिया परिवार लाभान्वित हुए है। जो इन तीनों योजनाओं की अपार सफलता को प्रदर्शित करता है। जबकि दोनों तहसीलों के दो–तिहाई से अधिक सहरिया परिवार माध्यमिक स्तर (कक्षा– VI से XII) के विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्प्रेरक से सम्बन्धित मुफ्त स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फीस वितरण, प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति तथा उपस्थिति प्रोत्साहन की योजनाओं से लाभान्वित हुए

j[kkfp= 5% 'kkgkckn e 'k{kf.kd fodkl ls lEcfU/kr ;kstukvksa ls ykHkkfUor

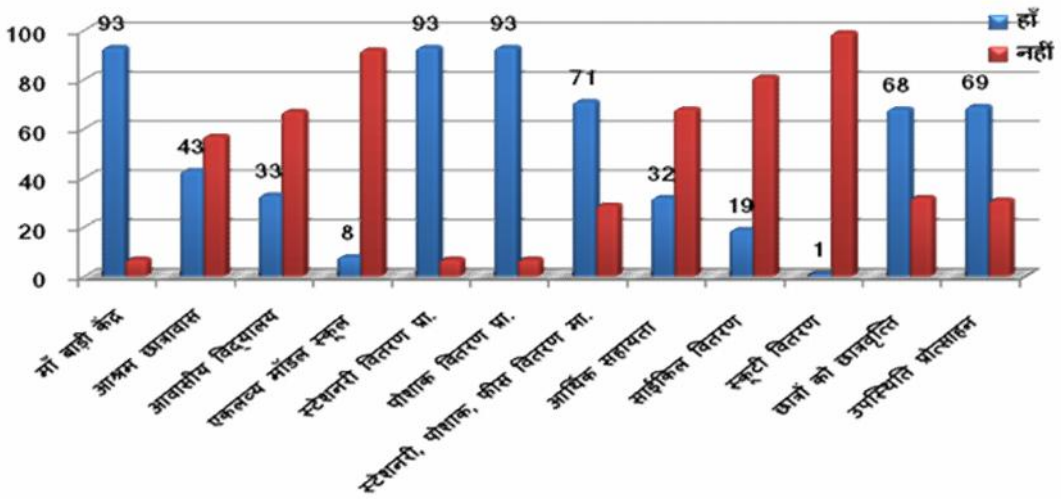

है जो यह सिद्ध करता है कि ये तीनों योजनाएं अपने–अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी सीमा तक सफल रही है। लाभार्थियों की संख्या की दृष्टि से उपयुक्त योजनाओं के अलावा शेष बची छः योजनाओं का प्रदर्शन अधिक उत्साहवर्धक नहीं है। जहाँ एक ओर दोनों तहसीलों में इनमें से तीन योजनाओं– सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, आश्रम छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों का प्रदर्शन औसत से कम है क्योंकि इन तीनों योजनाओं से लाभ अर्जित करने वाले लाभार्थियों का अनुपात दोनों ही तहसीलों में 25% से 43% के मध्य है जो कि इन योजनाओं के असंतोषजनक प्रदर्शन को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर दोनों ही तहसीलों में लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से एकलव्य मॉडल स्कूल का संचालन, सहरिया छात्राओं को निःशुल्क साइकिल (कक्षा–9 से 12) तथा स्कूटी के वितरण की योजनाओं का प्रदर्शन 20% से भी कम रहा है जो कि अत्यंत निराशाजनक है।

;kstukvksa dk çHkko

सहरिया विकास परियोजना के अंतर्गत सहरिया जनजाति के शैक्षिक उत्थान हेतु संचालित शैक्षणिक विकास की विभिन्न शासकीय योजनाओं के संदर्भ में सहरिया जनजाति के परिवारों की शिक्षा के स्तर, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच कर प्राप्त परिणामों को सारणी 4 तथा रेखाचित्र 6 में रखने पर यह स्पष्ट होता है कि सहरियों की

lkj.kh 4% 'k{kf.kd fodkl dh ;kstukvksa dk lgfj;ksa ij çHkko

en	fd'kuxat ¼100½		'kkgkckn ¼100½		dqy
	of)	dkbZ çHkko ugha	of)	dkbZ çHkko ugha	
शिक्षा का स्तर	92	08	97	03	200
अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता	81	19	91	09	200
स्वास्थ्य का स्तर	82	18	92	08	200

शैक्षणिक उन्नति पर विभिन्न शासकीय योजनाओं का अत्याधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जहाँ एक ओर किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों के क्रमशः 92% तथा 97% सहरिया जनजाति के परिवारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन योजनाओं के संचालन से उनकी शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर इन योजनाओं के संचालन के परिणामस्वरूप अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में हुई वृद्धि की बात को किशनगंज तहसील के 81% तथा शाहाबाद तहसील के 91% सहरिया परिवारों ने स्वीकार किया है। यहीं नहीं शैक्षणिक विकास की विभिन्न शासकीय योजनाओं से उनके स्वास्थ्य के स्तर में हुई वृद्धि की बात को किशनगंज तथा शाहाबाद तहसीलों की क्रमशः 82% तथा 92% सहरिया आबादी ने स्वीकारा है।

j[kkfp= 6% 'k{kf.kd fodkl dh ;kstukvksa dk lgfj;ksa ij çHkko

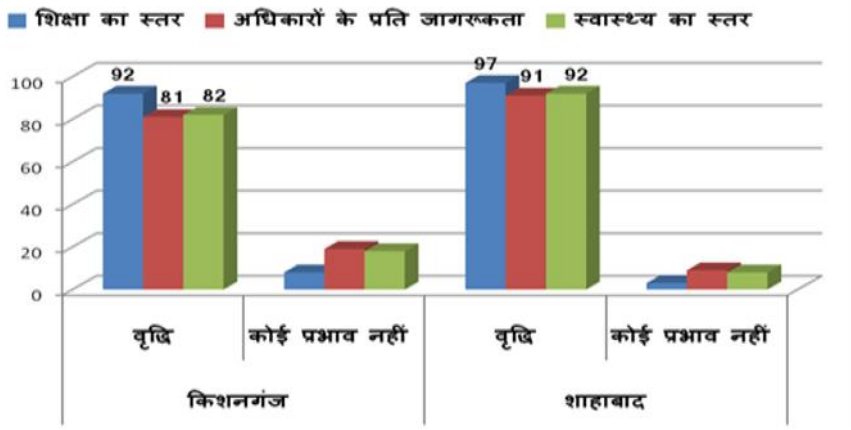

fu"d"k

राजस्थान की सहरिया जनजाति के शैक्षणिक उन्नयन के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं का प्राथमिक समंकों के आधार पर किया गया उपर्युक्त अध्ययन यह निष्कर्ष देता है कि सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए माँ–बाड़ी केंद्रों का संचालन, मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा– I से V), मुफ्त पोशाक वितरण (कक्षा– I से V), मुफ्त स्टेशनरी, पोशाक एवं स्कूल फीस वितरण (कक्षा– VI से XII), प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति तथा उपस्थिति प्रोत्साहन आदि छः योजनाओं का प्रदर्शन जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से उत्कृष्ट स्तर का रहा है। इस प्रकार बारह में से छः योजनाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन यह दर्शाता है कि सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए सरकार द्वारा किये गए कार्य सराहनीय है। शैक्षणिक विकास की तीन योजनाओं– सहरिया छात्राओं को आर्थिक सहायता, आश्रम छात्रावासों तथा आवासीय

विद्यालयों के संचालन का प्रदर्शन, जानकारी के अनुपात की दृष्टि से तो सामान्य है, परन्तु लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से असंतोषजनक है। इन आश्रम छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं जैसे कि – भोजन, पेयजल, आवास तथा कठिन विषयों की अतिरिक्त कक्षाओं के बारे में वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा स्थानीय सहरियों से बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि इन सुविधाओं में विशेषकर पेयजल तथा भोजन की गुणवत्ता में सुधार किया जाना अपेक्षित है। वहीं दूसरी ओर एकलव्य मॉडल स्कूल के संचालन, सहरिया छात्राओं को निःशुल्क साइकिल (कक्षा–9 से 12), तथा स्कूटी के वितरण की योजनाओं का प्रदर्शन, जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से निराशाजनक रहा है। इनमें से दो योजनाएँ सहरिया जनजाति की बालिकाओं के लिए संचालित है। अतः इन योजनाओं का कमजोर प्रदर्शन यह दर्शाता है कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में सहरियों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक कमजोर है। इसलिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा इन योजनाओं तथा बालिका शिक्षा के बारे में अधिक प्रचार–प्रसार कर सहरिया लोगों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है।

उपर्युक्त सभी योजनाओं में से जानकारी तथा लाभार्थियों के अनुपात की दृष्टि से क्रमशः आवासीय विद्यालयों के संचालन तथा सहरिया छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी वितरण की योजनाओं को छोड़कर शेष सभी योजनाओं में शाहाबाद का प्रदर्शन किशनगंज की अपेक्षा बेहतर है। इसका मुख्य कारण सहरिया विकास परियोजना से सम्बन्धित अधिकतर सरकारी कार्यालयों तथा संस्थानों की अवस्थिति शाहाबाद में होना है। यहीं नहीं सहरियों के शैक्षणिक विकास की विभिन्न योजनाओं का उनके शिक्षा के स्तर, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा स्वास्थ्य के स्तर में हुई वृद्धि के मामले में भी शाहाबाद का प्रदर्शन किशनगंज की अपेक्षा अधिक संतोषजनक है। अतः सहरिया विकास परियोजना से जुड़े नीति–निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा भविष्य में सहरियों के शैक्षणिक विकास के लिए किशनगंज में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्कता है।

I nHk xUFk I ph

1. वार्षिक रिपोर्ट (2019–20), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
2. सेंसस (2011), प्राइमरी सेंसस एब्स्ट्रेक्ट डाटा फॉर शेड्यूल्ड ट्राइबस (ST) (India & States/UT's - District Level), ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट आफ इंडिया,
3. सती, वी. पी. (2015), सहरिया ट्राइबः सोसायटी, कल्चर, इकोनॉमी एंड हैबिटेशन, एनल्स ऑफ नेचुरल साइंसेज, वॉल्यूम– I(1), (दिसंबर 2015), पृ.सं. 26–31.
4. जैग्सा, वी. (2015), लेबर मार्केट एण्ड आदिवासीः एन ओवरव्यू, एस. आर. शंकरण चेयर, कॉफ्रेंस सीरीज, एन.आई.आर.डी., हैदराबाद, पृ.सं. 6–22.
5. घोष, ए. के. (2007), झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों के मध्य साक्षरता तथा शिक्षा में लैंगिक अंतराल, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन वॉल्यूम– XVI(1), पृ.सं. 109–125.
6. गौत्तम, डॉ. एन. (2013), भारत में अनुसूचित जनजाति की शिक्षाः योजनाएँ तथा कार्यक्रम, जर्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड प्रैक्टिस, वॉल्यूम– IV, नंबर– 04, पृ.सं. 07–10.
7. दरीपा, एस. एम. (2017), ट्राइबल एजुकेशन इन इण्डियाः गवर्नमेंट इनिशिएटिव एण्ड चैलेंजेस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंसेज, वॉल्यूम– VII, इशू–10, (अक्टूबर, 2017), पृ.सं. 156–166.
8. स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इण्डिया (2013), मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, वेबसाइट www.tribal.nic.in, पृ.सं. 13–25.
9. पटेल, एस. (1991), ट्राइबल एजुकेशन इन इण्डिया, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 03–22.

❖◆❖